THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) At present there is no information of Maharashtra Government's having exempted Tata Indica Car from sales tax.

(b) and (c) Do not arise. However, it may be stated that there is no price regulation or control in the Automotive sector.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

2052. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम हैं, जिनके कर्मचारियों को बहुत दिनों से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उपर्युक्त कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान करने के लिए कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ रूग्ण उपक्रमों में मजूरी की अदायगी की राशि बकाया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले कुछ मंत्रालयों से प्राप्त अनन्तिम सूचना के आधार पर सितम्बर, 1998 को समाप्त तिमाही को मजूरी तथा वेतन के कारण कुल बकाया देनदारी लगभग 100 करोड़ रुपए है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्रीय बजट 1999-2000 में आयोजना भिन्न ऋणों के लिएं 1735 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जोकि मुख्यतः रूग्ण तथा सुधार कर रहे उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन तथा मजूरी की अदायगी के लिए है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार

2053. **प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से कितने लोग लाभान्वित हुए और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस उद्योग के माध्यम से और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1997-98 तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 56.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है जिसमें खादी के अन्तर्गत 14.01 लाख तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 42.49 लाख व्यक्ति हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की पूरी संभाव्ता का उपयोग करने के लिए, 2 मिलियन व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लक्ष्य सहित, वर्ष 1995-96 में एक नये कार्यक्रम नामतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से लाभान्वित राज्यवार व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्तर्गत राज्यवार रोजगार 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98

(रोजगार लाख व्यक्ति)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
	राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.53	3.59	3.60
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	0.01

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
3.	असम	1.04	1.13	1.11
4.	बिहार	3.36	3.50	3.75
5.	गोवा	0.06	0.05	0.05
6.	गुजरात	1.00	1.07	1.07
7.	हरियाणा	0.96	0.95	0.92
8.	हिमाचल प्रदेश	0.88	0.93	0.79
9.	जम्मू और कश्मीर	0.87	0.85	0.96
10.	कर्नाटक	1.98	1.98	2.33
11.	केरल	2.09	2.12	2.32
12.	मध्य प्रदेश	1.10	1.25	1.16
13.	महाराष्ट्र	4.74	4.76	4.00
14.	मणिपुर	0.37	0.43	0.42
15.	मेघालय	0.12	0.13	0.13
16.	मिजोरम	0.09	0.11	0.12
17.	नागालैंड	0.11	0.18	0.19
18.	उड़ीसा	2.06	2.05	2.10
19.	पंजाब	1.72	1.85	1.84
20.	राजस्थान	3.91	4.06	4.41
21.	सिक्किम	0.05	0.04	0.05
22.	तमिलनाडु	11.05	11.38	10.91
23.	त्रिपुरा	0.49	0.26	0.27

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
24.	उत्तर प्रदेश	11.36	11.61	10.21
25.	पश्चिम बंगाल	3.49	3.61	3.51
	योग-I	56.43	57.89	56.23
II.	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार	*	*	*
2.	चंडीगढ़	0.02	0.03	0.04
3.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
4.	दमन और द्वीव	—	—	—
5.	दिल्ली	0.23	0.21	0.18
6.	लक्षद्वीप	—	*	*
7.	पांडिचेरी	0.04	0.04	0.05
	योग-II	0.29	0.28	0.27
	योग-I + II	56.72	58.17	56.50

* 500 से कम

Review of reservation list for SSIs

2054. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the PHD Chamber of Commerce and Industry has called upon Government for reviewing the reservation list for Small Scale Industries prepared by Abid Hussain Committee, and laying down clear norms and rationale for the purpose; and

(b) if so, what is Government's response thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Foreign equity in passenger cars

2055. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has approved a proposal to allow foreign equity investments upto 74 per cent in the passenger car sector;

(b) if so, the reasons therefor;